दिल्ली के किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना

*116. **श्री सज्जन कुमार** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्वेत क्रान्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की दिल्ली के किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने की कोई योजना है ताकि वे अच्छी नसल की भैंसें और गाय खरीद सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशुओं की खरीद के लिए सामान्य दरों पर अर्थात् छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों व कृषि श्रमिकों के लिए 33-1/3 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। शेष धनराशि सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है जिसके लिए ब्याज देना पड़ता है।

(ख) दिल्ली में, गत तीन वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए 5552 लाभभोगियों में से 3505 को दुधारू पशुओं के रूप में सहायता दी गई है।

Housing by D.D.A.

*117. SHRI JAGPAL SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) to what extent the D. D. A. has been able to meet the growing housing need in the Capital and in checking the speculation in land prices ;

(b) what is the present backlog and the number of houses D. D. A. is required to build annually to clear the backlog within the next five years or so ;

(c) whether with the growing housing demand and DDA's incapability to meet the requirement, there is any proposal with the Government to involve the private builders in the housing activities ; and

(d) if so, the decision, if any taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : (a) To a considerable extent, the DDA has been able to satisfy the demand for houses and also check speculation in land prices.

(b) Though no precise survey has been conducted, it is estimated that the backlog/shortage of houses in Delhi is around four lakhs dwelling units. It is expected that the housing programmes of the DDA coupled with construction activities of other Government Organisations, Cooperative Group Housing Societies etc. would lead to an appreciable reduction in the backlog during the next five years.

(c) and (d). Certain proposals suggesting involvement of private builders in land development and construction of dwelling units have been recently received from an association of private builders in Delhi and is being examined.